Publication	The Hindu Business Line	Language	English
Edition	New Delhi	Journalist	Prabhudatta Mishra
Date	14/01/2023	Page no	1, 8

SOWING SEEDS OF GROWTH.

IFFCO may anchor new co-operative — Bharatiya Sahakari Beej Samit — to tap the ₹40,000-crore Indian seed market **p8**

Internal (for authorised circulation only)

Downloaded from SAMVAD

IFFCO may anchor new co-op to tap ₹40,000-crore seed market

GAME-CHANGER. New entity may rope in 63,000 PACs for retailing, pose a challenge to the private sector

Prabhudatta Mishra
New Delhi

A new seed co-operative proposed to be named Bharatiya Sahakari Beej Samit (BSBS) is likely to start operating this month, potentially taking away a sizeable revenue from the private sector in the ₹36,000-crore domestic seed market.

Earlier this week, the Union Cabinet approved the establishment of the multi-State seed co-operative society along with a national export society and a national co-operative society for organic products.

The co-operative will be located inside IFFCO's corporate office. The co-operative has officially been mandated to tap the potential in the unexplored ₹40,000-crore seed market. Farmers will use a part of their own crop as seeds, while BSBS will dent the existing market dominated by the private sector when it launches its operations, experts said.

SHARE CAPITAL

"The Government is facilitating its formation and there will be no direct shareholding. All the 63,000 primary agricultural credit societies (PACS) will be roped in to retail the seeds to be sold by the new multi-state co-operative," said Gyanesh Kumar, Secretary, Co-operation.

He said BSBS will have an authorised share capital of ₹500 crore.

IFFCO may play the role of anchor promoter given its wide reach through a network of thousands of co-operatives at village levels, sources said.

The National Seeds Corporation and Indian Council of Agricultural Research (ICAR) will be co-opted on the BSBS board as expert members. ICAR has been asked by the Government to provide breeder seeds and technological support to the new co-operative to kick-start its activities.

SEEDS OF GROWTH. The co-operative has the potential to sell 415 lakh quintals of seeds

Of the annual requirement of 787 lakh quintals seeds, the actual availability through organised retails is about 372 lakh quintals, leaving an untapped potential for 415 lakh quintals which come from the farmers' own crops as well as from neighbours, officials said.

"It has been seen that there is 15-20 per cent yield improvement when farmers move to certified seeds from farm-saved seed (FSS)," Kumar said. As many as 29 crore members of co-operative societies, largely marginal farmers and people from lower income groups in rural areas will be the target of BSBS so that quality inputs reach them at least or no cost, the official said. Many of the Central schemes in seed distribution may also be routed through BSBS, the official said.

Internal (for authorised circulation only)

Downloaded from SAMVAD

Publication	Dainik Jagran	Language	Hindi
Edition	New Delhi	Journalist	Surendra Prasad Singh
Date	14/01/2023	Page no	9

पारदर्शिता और भरोसे के साथ सशक्त होगा सहकारी ढांचा

सुरेंद्र प्रसाद सिंह ● नई दिल्ली

- राष्ट्रीय सहकारी नीति पर गठित समिति के साथ शाह ने की चर्चा
- सुरेश प्रभु की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति तैयार कर रही नीति का प्रारूप

पारदर्शिता, जवाबदेही, भरोसा और मजबूत संस्थागत ढांचा। इस ध्येय के साथ देश में सहकारी आंदोलन को एक नई धार दी जाएगी। उद्देश्य यही है कि निचले स्तर से लेकर शीर्ष सहकारी संस्थाएं तक कारगर बनें, वक्त की जरूरत भी पूरी करें। लोगों का उन पर भरोसा भी दृढ़ हो। इसी कड़ी के तहत देश में सहकारी आंदोलन को डिजिटल बनाने से लेकर उसे प्रभावशाली स्वरूप देने का काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए राष्ट्रीय सहकारी नीति का प्रारूप तैयार करने का काम तेज कर दिया गया है। दरअसल, इसकी पहल केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में 47 सदस्यीय राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति का गठन कर की थी। सहकारिता मंत्रालय में विशेषज्ञ समिति की गुरुवार को हुई बैठक में शाह ने भी हिस्सा लिया, जिसमें समिति की अब तक की प्रगति की समीक्षा की गई।

सूत्रों के मुताबिक, बैठक में निचले स्तर की सहकारी समितियों से लेकर शीर्ष सहकारी संस्थाओं के कामकाज में पारदर्शिता लाने पर जोर दिया गया। समितियों के गठन और उनके चुनावों को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाएगा। राष्ट्रीय सहकारी नीति के प्रारूप में दो दशक पहले (2002) बनी नीतियों में कई तरह के संशोधन किए जा सकते हैं। विशेषज्ञ समिति को मंत्रालय की ओर से नई राष्ट्रीय नीति में 'सहकार से समृद्धि' का सूत्र वाक्य दे दिया गया है। सहकारी समितियों में जमीनी स्तर के कोआपरेटर (सहकार) की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी।

राष्ट्रीय सहकारी नीति के प्रस्तावित मसौदे में सहकारिता के माध्यम से आर्थिक विकास के माडल को शामिल किया जाएगा। सहकारिता आंदोलन के माध्यम से लीगल और इंस्टीट्यूशनल ढांचा तैयार करने वाले प्रविधानों को जगह दी जाएगी। सहकारिता मंत्री शाह कई मंचों पर इस बात को दोहरा चुके हैं कि देश के सहकारी आंदोलन के सहारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सकता है। इसके लिए लोगों का भरोसा जीतना होगा। इसी से सहकारी क्षेत्र की संस्थाओं में लोगों का भरोसा बढ़ेगा। 2002 की राष्ट्रीय सहकारी नीति में तब की जरूरतों के हिसाब से प्रविधान किए गए थे, जिसके चलते सहकारी आंदोलन को बल मिला, लेकिन अब सहकारी संस्थाओं की बढ़ते दायरे के अनुरूप मौजूदा डिजिटल क्रांति के उपयोग से इसकी गति को और बढ़ाया जा सकता है। देश में 8.5 लाख सहकारी समितियां और 29 करोड़ से अधिक उसके सदस्य हो चुके हैं। इसमें विभिन्न तरह की गतिविधियां भी बढ़ी हैं, जिन्हें सहयोग व समर्थन की जरूरत है।

****

Internal (for authorised circulation only)

Downloaded from SAMVAD